

सं० ओ०वि०/फरीदाबाद/56-83/58444.—चूँकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज अमर इन्जीनियरिंग वर्क्स प्लॉट नं० 106, सेक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राजेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं;

क्या श्री राजेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ०वि०/सोनीपत/163-83/58396.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड सब अरबन डिविजन फाजिलपुर (सोनीपत) के श्रमिक श्री प्रताप सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम-70/32573, दिनांक 6-11-1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) अम-70/13648, दिनांक 8-5-70 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री प्रताप सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ०वि०/सोनीपत/134-83/58451.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज कार्यकारी अभियन्ता सब, अरबन डिविजन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड फाजिलपुर (सोनीपत) के श्रमिक श्री हवा सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूँकि हरियाणा राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम-70/32573, दिनांक 6-11-1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) अम/70/13648, दिनांक 8-5-70 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है:—

क्या श्री हवा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

बी० एस० चौधरी,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।